- 19th Year
- Issue: 302
- 14.03.2026 (SATURDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

असम में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले-झूठे वादों की है दुकान, समुदायों के बीच पैदा किया विभाजन

गुवाहाटी १३/०३ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनाव वाले असम में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर विभिन्न समुदायों में फूट डालने का आरोप लगाया और उसे झूठे वादों की दुकान करार दिया। गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोकराझार में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बोडोलैंड की कई पीढ़ियों को झूठे सपनों में उलझाए रखा। मोदी ने कहा कि जब आपने कांग्रेस को देश और असम दोनों से सज़ा से बेदखल कर भाजपा-एनडीए को सज़ा सौंपी, तो हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास शुरू किए।

कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न समुदायों में फूट डाली, जबकि भाजपा ने स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में काम किया। इसी सोच के साथ बोडो शांति समझौता हुआ था। पहली बार इस समझौते ने सभी प्रमुख संगठनों और समूहों को एक साथ लाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादों की दुकान है—और हर झूठे वादे के साथ, यह चार 'बड़े झूठ' बोनस उपहार के रूप में देती है। ऐसा इसलिए है ज़्योंकि कांग्रेस का उन वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए की दो इंजन वाली सरकार असम की विरासत के संरक्षण और राज्य के तीव्र विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने पिछले कुछ दशकों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया है; इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज, बोडोलैंड शांति और विकास के पथ पर अग्रसर है। आज, असम शांति और प्रगति का एक नया अध्याय लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बोडो समुदाय द्वारा अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित देखकर उन्हें गर्व होता है। उन्होंने कहा कि आपका प्रेम मेरे ऊपर एक ऋण के समान है, और मेरा उद्देश्य हमेशा से आपकी सेवा करके और इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करके इस ऋण को चुकाना रहा है। कुछ सप्ताह पहले, मुझे गुवाहाटी में समृद्ध बोडो संस्कृति को देखने का अवसर मिला। आज इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और आधारशिला रखी गई है। कोकराझार और पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ खोया भी है। हमने वो कठिन समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बमों और तोपों की आवाज गूंजती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास के पथ पर अग्रसर है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए विभिन्न समुदायों में फूट डालती थी, जबकि भाजपा ने शांति के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि 2020 के समझौते के तहत किए गए सभी वादे निरंतर प्रयासों से एक-एक करके पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बोडोलैंड के लिए 1,500 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज उपलज़्ध कराया गया है। आज कोकराझार में एक मेडिकल कॉलेज चल रहा है। वे सभी माताएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं जिनके बेटे घर लौट आए हैं और अब अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्वक और खुशी से रह रहे हैं।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास, इतिहास में पहली बार हटाने का प्रस्ताव संसद में पेश

१३/०३ (संवाददाता): विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में नोटिस जमा कर मुज़्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की मांग की है। सूत्रों के हवाले से मिली रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा में 130 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहली बार है कि किसी मुज़्य चुनाव आयुक्त को संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से हटाने का अनुरोध किया जा रहा है। सांसदों ने एसआईआर प्रक्रिया के संचालन में गंभीर खामियों का आरोप लगाया, जिससे उनके अनुसार चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता हुआ है।

सूत्रों ने कहा, हस्ताक्षरकर्ताओं में 'इंडिया' गठबंधन के सभी घटक दलों के सदस्य शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। आम आदमी पार्टी अब औपचारिक रूप से विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हालांकि उसने इस कदम का समर्थन किया है। सूत्रों ने बताया कि कुछ निर्दलीय सांसदों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नियमों के मुताबिक, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नोटिस और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर नोटिस देना होता है।

विपक्षी दलों ने कई मौकों पर सीईसी पर सज़ारूढ़ भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। विपक्ष मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद को लेकर पिछले कुछ महीनों से उन पर लगातार निशाना साधता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर का उद्देश्य भाजपा की मदद करना है। सीईसी को पद से हटाने का नोटिस संसद के किसी भी सदन में दिया जा सकता है और इसे अवश्य ही विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए।

एलपीजी पर राहुल गांधी के दावे, गिरिराज सिंह का पलटवार-देश में भ्रम फैलाना उनकी आदत है

नयी दिल्ली १३/०३ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने और वैश्विक मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने की आदत होने का आरोप लगाया। संसद के बाहर एएनआई से बात करते हुए सिंह ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यह आदत बन गई है कि वे देश में भ्रम फैलाते हैं और विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं। मकर द्वार पर चाय पीते हुए और देश का अपमान करते हुए उन्होंने कोविड के दौरान भी देश में भ्रम फैलाया।

उनकी ये टिप्पणियां केंद्र और विपक्ष के बीच राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चल रही तीखी बहस के बीच आई हैं, जिसे पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति पर इसके प्रभाव ने और हवा दी है। एक दिन पहले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और कहा था कि दर्द तो अभी शुरू हुआ है।

लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने कहा कि अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के वैश्विक और घरेलू स्तर पर दूरगामी परिणाम होने की संभावना है। गांधी ने चेतावनी दी कि इसका असर देश भर में महसूस होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि रेस्तरां बंद हो रहे हैं और एलपीजी की उपलज़्धता को लेकर लोगों में दहशत बढ़ रही है। उन्होंने कहा,मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका, इज़राइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होंगे। होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे वैश्विक तेल का 20ल प्रवाह होता है, बंद कर दिया गया है।

महुआ मोइत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एज़्शन

कोलकाता १३/०३ (संवाददाता): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लोकपाल को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी देने की अनुमति दी गई थी। भारत के मुज़्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ लोकपाल की याचिका पर मोइत्रा, केंद्रीय जांच ज़्यूरो (सीबीआई) और भाजपा सांसद तथा शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया। 19 दिसंबर 2025 को, उच्च न्यायालय ने लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें सीबीआई को कथित पूछताछ के बदले नकद घोटाले में मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने उस निर्णय के पैरा 89 में कहा था माननीय लोकपाल से अनुरोध है कि वे लोकपाल अधिनियम की धारा 20 के तहत स्वीकृति प्रदान करने के लिए, ऊपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार, आज से एक महीने की अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करें।मुज़्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकपाल अधिनियम की धारा 20 के तहत सूचीबद्ध शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित कई याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 89 पर रोक लगा दी।

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का मास्टरस्ट्रोक, 5 नए विकास बोर्ड बनाने का ऐलान

कोलकाता १३/०३ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राज्य के हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए पांच नए सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये बोर्ड उनकी अनूठी भाषाओं और परंपराओं की रक्षा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सुनिश्चित करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ने लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार जल्द ही मुंडा (अनुसूचित जनजाति), कोरा (अनुसूचित जनजाति), डोम (अनुसूचित जनजाति), कुंभकार (अन्य पिछड़ा वर्ग) और सदगोपे (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदायों के लिए पांच नए सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डों का गठन करने जा रही है। ये समुदाय बंगाल की जीवंत संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देती हूं।

उन्होंने आगे कहा कि इन बोर्डों का उद्देश्य पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना और समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। ये बोर्ड उनकी अनूठी भाषाओं और परंपराओं की रक्षा करते हुए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सुनिश्चित करेंगे। वे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और आगे सामाजिक-आर्थिक विकास लाएंगे। 2013 से हमने अपने कमजोर समुदायों के लिए ऐसे कई बोर्ड स्थापित किए हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हैं। एज़्स पर पोस्ट में लिखा था कि मां, माटी, मानुष के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अर्थ है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे। हमारा लक्ष्य सरल है- समावेशी प्रगति और अटूट समर्थन के माध्यम से हर चेहरे पर मुस्कान लाना। जय बांग्ला।

यह 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी, जो पिछले चुनावों में 77 सीटें जीतने के बाद इस बार भी जीत हासिल करना चाहेगी।

लखनऊ और बडगाम में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन

लखनऊ १३/०३ (संवाददाता):यौम-ए-कुद्स के अवसर पर जज़्मू एवं कश्मीर के बडगाम में हजारों लोग एकत्रित हुए और फिलिस्तीन और ईरान के उत्पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए विरोध मार्च निकाला। बडगाम के मरकज़ी इमामबाड़ा में भारी जनसमूह इकट्ठा हुआ, जिसके बाद लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकाली और बुडगाम के मुज़्य चौक की ओर मार्च किया। शुक्रवार को लखनऊ के बारा इमामबाड़ा में जुज़्मे की नमाज के बाद लोगों के इकट्ठा होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद नकवी ने किया, जिन्होंने अमेरिका की आलोचना करते हुए ईरान से जुड़े संघर्ष को लेकर उसकी कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करने की मांग की। एएनआई से बात करते हुए कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि ईरान पूरी तरह से बेसहारा है; अमेरिका उस पर बम गिरा रहा है और जनता पर हमले कर रहा है। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारा देश इसकी निंदा नहीं कर रहा है। हमारे देश ने ईरान के प्रति इतना बुरा रवैया अपनाया है कि ईरानी हम पर दया दिखा रहे हैं। उन्होंने भारत को अपने तेल जहाजों को लाने की अनुमति दी है... अमेरिका को हमले करने से रोका जाना चाहिए। अन्यथा, पूरी दुनिया को अमेरिका और इज़राइल का बहिष्कार करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और ईरान का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह पहल बहुत देर से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले बात करनी चाहिए थी; अब इसका कोई मतलब नहीं है।

मासिक धर्म अवकाश के मुद्दे पर सुको ने दखल देने से कर दिया इंकार, सरकार पर छोड़ा फैसला

नयी दिल्ली १३/०३ (संवाददाता): देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें महिलाओं और छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने के लिए पूरे देश में एक समान नीति बनाने की मांग की गयी थी। अदालत ने इस विषय पर विस्तृत सुनवाई नहीं की, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण बताते हुए कहा कि इस तरह का निर्णय न्यायालय की बजाय नीति बनाने वाले संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में आता है।मुज़्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि मासिक धर्म अवकाश को कानून के माध्यम से अनिवार्य बना दिया गया तो इसके अनपेक्षित परिणाम सामने आ सकते हैं। अदालत का मानना था कि इससे महिलाओं के रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सुनवाई के दौरान मुज़्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि किसी संस्था या कंपनी द्वारा स्वेच्छा से ऐसा अवकाश दिया जाता है तो यह स्वागत योग्य है, लेकिन यदि इसे कानून द्वारा अनिवार्य बना दिया गया तो कई नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से हिचक सकते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा कदम महिलाओं की सहायता करने की बजाय उनके पेशेवर अवसरों को सीमित भी कर सकता है। पीठ ने यह भी चिंता व्यक्त की कि मासिक धर्म को अवकाश का कानूनी आधार बनाने से महिलाओं के बारे में गलत धारणाएं मजबूत हो सकती हैं। न्यायालय का कहना था कि इससे यह संदेश जा सकता है कि महिलाएं कार्यस्थलों पर कम सक्षम या कम भरोसेमंद हैं। अदालत ने कहा कि इस प्रकार की दलीलें कई बार महिलाओं को कमतर दिखाने की आशंका पैदा करती हैं, जबकि मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की नीतियां बनाने का अधिकार सरकार और नीति निर्माताओं के पास है। विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद ही ऐसी नीति तैयार की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता पहले ही इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को एक प्रतिवेदन दे चुके हैं। इसलिए सक्षम प्राधिकारी उस प्रतिवेदन की जांच कर सकता है और आवश्यकता समझे तो परामर्श के बाद कोई नीति बना सकता है। इसी आधार पर न्यायालय ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया और कोई अतिरिक्त निर्देश देने से परहेज किया।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने तर्क दिया कि देश के कुछ हिस्सों में पहले से ही मासिक धर्म अवकाश की व्यवस्था लागू है। उन्होंने बताया कि केरल में कुछ शिक्षण संस्थानों ने मासिक धर्म के दौरान छात्राओं को विशेष छूट देने की व्यवस्था की है। इसके अलावा कई निजी कंपनियों ने भी स्वेच्छा से ऐसी नीतियां लागू की हैं। हालांकि न्यायालय ने इन उदाहरणों को स्वीकार करते हुए भी यह कहा कि स्वैच्छिक व्यवस्था को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत के अनुसार यदि संस्थान और कंपनियां स्वयं इस दिशा में पहल करती हैं तो यह अधिक व्यावहारिक और संतुलित समाधान हो सकता है। देखा जाये तो सर्वोच्च न्यायालय के इस रुख के कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। अदालत ने यह संकेत दिया है कि सामाजिक और श्रम संबंधी जटिल मुद्दों का समाधान केवल न्यायिक आदेशों से नहीं बल्कि व्यापक नीति निर्माण से होना चाहिए। इससे सरकार और समाज दोनों की जिज़्मेदारी बढ़ जाती है कि वे महिलाओं की आवश्यकताओं को समझते हुए संतुलित व्यवस्था तैयार करें। साथ ही अदालत ने रोजगार के क्षेत्र में संभावित दुष्परिणामों की ओर ध्यान दिलाया है। यदि अनिवार्य अवकाश कानून बना दिया जाता है तो कुछ नियोक्ता महिलाओं को नियुक्त करने से बच सकते हैं। इससे लैंगिक समानता के लक्ष्य को नुकसान पहुंच सकता है।इसके अलावा, यह फैसला इस बहस को भी रेखांकित करता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल की समानता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाये। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं वास्तविक हैं, लेकिन नीति बनाते समय यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे महिलाओं की पेशेवर छवि कमजोर न हो। कुल मिलाकर देखें तो अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मासिक धर्म अवकाश का मुद्दा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसका समाधान न्यायिक आदेश के बजाय व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक संवाद से निकलना चाहिए। अब निगाहें सरकार और नीति निर्माताओं पर रहेंगी कि वे इस विषय पर आगे ज़्या कदम उठाते हैं।

विविध समाचार

संसद में एलपीजी संकट पर विपक्ष का हल्लाबोल, ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

नयी दिल्ली १३/०३ (संवाददाता): बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला सप्ताह आज खत्म हो गया। संसद के दोनों सदनों को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार को, सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में मुज़्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाले नोटिस सौंपे और विपक्ष ने एलपीजी संकट को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को केंद्र से देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की, वहीं सज़ाधारी गठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में 18 निजी विधेयक पेश हुए जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के योगदान संबंधी प्रावधान वाला विधेयक भी शामिल है। कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। लोकसभा ने विज़ वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को पारित किया। विज़ मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि एक लाख

करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (इकोनॉमिक स्टेबिलाइज़ेशन फंड) सरकारी योजनाओं को पटरी से उतारे बिना मौजूदा वैश्विक संकट जैसी स्थिति में देश को आर्थिक झटकों को सहन करने में मदद करेगा। लोकसभा में विज़ वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विज़ मंत्री ने कहा कि यह कोष पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट जैसी आकस्मिक वैश्विक चुनौतियों से लगने वाले झटकों को झेलने के लिए एक 'बफर' के तौर पर काम करेगा।

विज़ मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शुक्रवार को कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में उज़र प्रदेश के नगीना निर्वाचन क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सांसद को अपना नाम चंद्रशेखर 'रावण' की जगह चंद्रशेखर 'विदुर' रखने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि 'महाभारत' में एक बहुत सज़्मानित व्यक्तित्व हैं, जिनका नाम विदुर है और जिनकी विद्वता का सभी लोग सज़्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हाल में पता चला है कि विदुर ने अपने जीवन का आखिरी समय बिजनौर में बिताया था।जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा है कि भारत के महापंजीयक कार्यालय ने गंगोता समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने संबंधी बिहार सरकार के प्रस्ताव का औचित्य बताने को कहा है। उइके ने बताया कि बिहार सरकार ने चार नवंबर 2019 को एक नृजातीय रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव भेजा था।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने शुक्रवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार अच्छे स्लोगन बनाने में सभी देशों को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है ज़्योंकि यह ठोस परिणाम नहीं दे सकी है। ओ'ब्रायन ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि बड़े-बड़े स्लोगन बनाने के बावजूद भारत बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।

निजी अस्पतालों में महंगे इलाज और निजी एवं चिकित्सा बीमा कंपनियों द्वारा मरीजों के दावे मनमाने तरीके से खारिज किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मांग की कि इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए स्वाति ने कहा कि आज निजी अस्पतालों और निजी बीमा कंपनियों के बीच गठजोड़ बन गया है जो आम इंसान की कमर तोड़ रहा है।

ज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के राजीव शुज़्ला ने कृषि बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को संकट के समय समुचित राहत नहीं मिलने का दावा करते हुए कहा कि किसानों के दावों का समय पर और उचित भुगतान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए शुज़्ला ने कहा कि कृषि बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बड़े जोश से योजना शुरू की गई थी और कहा गया था कि किसानों को कम प्रीमियम पर संकट में बड़ी मदद मिलेगी।

एलपीजी की कमी के चलते देशभर में इंडज़्शन चूल्हे धड़ाधड़ बिक रहे

नयी दिल्ली १३/०३ (संवाददाता): पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और समुद्री मार्ग बाधित होने के कारण भारत में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर आशंका का माहौल बन गया है। इस स्थिति ने देशभर में घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की बुकिंग में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर लोग वैकल्पिक साधनों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं, जिसके चलते इंडज़्शन चूल्हों और अन्य बिजली आधारित खाना पकाने के उपकरणों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की जा रही है।

ई-कॉमर्स मंचों पर इंडज़्शन चूल्हों की मांग पिछले कुछ दिनों में कई गुना बढ़ गई है। कुछ मंचों पर बिक्री चार-पांच गुना तक पहुंच गई है, जबकि कुछ स्थानों पर मांग बीस गुना तक बढ़ने की खबर है। दिल्ली, कोलकाता और उज़र प्रदेश के कई इलाकों में यह बढ़ोतरी और भी अधिक देखी जा रही है। त्वरित आपूर्ति सेवाओं यानि क्विक कॉमर्स मंचों और किराना दुकानों पर भी इंडज़्शन चूल्हों की बिक्री लगभग दस गुना तक बढ़ी है। घरेलू उपभोक्ता एलपीजी की अनिश्चितता को देखते हुए बैकअप व्यवस्था के रूप में बिजली से चलने वाले उपकरण खरीद रहे हैं।

उधर, एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी से कई जगह बुकिंग प्रणाली भी प्रभावित हुई है। उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि फोन आधारित बुकिंग, मोबाइल एप और एसएमएस से बुकिंग वाले प्लेटफार्म पर सर्वर डाउन के संदेश आ रहे हैं। वितरकों के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में बुकिंग की संज़्या लगभग दस गुना तक बढ़ गई है, जिसके कारण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और पूरी तरह से आपूर्ति बंद नहीं हुई है। हालांकि लोग एलपीजी डीलरों के यहां लाइनों में लगे हुए हैं और शिकायतें कर रहे हैं। उधर, व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर हालांकि असर पड़ा है। होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग सेवाओं को सीमित मात्रा में गैस दी जा रही है, जिससे कई कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। केरल में उद्योग संगठनों ने आशंका जताई है कि गैस की कमी के कारण लगभग चालीस प्रतिशत रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत उपायों के तहत केरोसिन और कोयले को अस्थायी रूप से खाना पकाने के विकल्प के रूप में फिर से अनुमति दी है। राज्यों को अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया गया है और होटल उद्योग को एक माह के लिए बायोमास, आरडीएफ पेलेट और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपयोग की अनुमति देने को कहा गया है।

हम आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच अंतराल को भी बढ़ाकर पैंतालीस दिन कर दिया है ताकि मांग को नियंत्रित किया जा सके और सभी उपभोक्ताओं तक गैस की उपलज़्धता सुनिश्चित हो सके। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश में रोजाना लगभग पचास लाख सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं और पेट्रोल, डीजल सहित अन्य ईंधनों की आपूर्ति सामान्य है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि घबराकर अनावश्यक बुकिंग न करें।

इस बीच, उज़र प्रदेश के हापुड़ में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण भी पकड़ा गया है। पुलिस ने एक व्यक्ति के घर पर छापा मारकर अठारह भरे और चौदह खाली सिलेंडर बरामद किए। आरोप है कि वह विभिन्न वितरकों से सिलेंडर खरीदकर स्थानीय लोगों को अधिक कीमत पर बेच रहा था। अधिकारियों ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई आशंकाओं ने देश में एलपीजी को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन सरकार का कहना है कि आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

अडानी-एपस्टीन फाईल्स पर अमेरिका कर रहा ब्लैक मेल, पीएम मोदी पर राहुल गांधी का आरोप

नयी दिल्ली १३/०३ (संवाददाता): लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी आज बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाषण देने से पहले मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी शिक्षा के बारे में ज़्या कहते थे। वे संगठन के महत्व पर जोर देते थे।

और जब कांशीराम जी रात में उज़र प्रदेश का दौरा करते थे, तो वे अपने साथ कलम रखते थे। वे यह भी कहते थे कि कलम इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि समाज के 15 प्रतिशत लोगों को तो लाभ मिले ही, साथ ही 85 प्रतिशत लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए; उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अब ज़्या हो गया है?

राहुल ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा ने एक नई व्यवस्था शुरू कर दी है। भाजपा ने कलम को उसके ढक्कन से अलग कर दिया है। उन्होंने ढक्कन को कहीं फेंक दिया है—पता नहीं कहाँ—और अब वे सिर्फ कलम लेकर घूम रहे हैं। मैंने एक बार किसी और से इस बारे में बात की थी—हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा करना सही था या गलत—लेकिन मेरा मानना है कि अगर जवाहरलाल नेहरू आज जीवित होते, तो कांशीराम जी कांग्रेस के मुज़्यमंत्री होते। आज हम कांशीराम जी के संघर्ष, उनके विजन और भारत की राजनीति पर उनके प्रभाव को याद करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की एनर्जी सिज़्योरिटी से समझौता कर दिया है, ज़्योंकि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे?

मैंने संसद में एपस्टीन का नाम लिया तो स्पीकर ने मुझे बोलने से रोक दिया। मंत्री हरदीप पुरी पहले से ही ष्व्द्ब-श्चह्ल्श्वद्बद्धह्यद्दस्त्र हैं। इनका नाम एप्सटीन फ़ाइलों में है और ये एप्सटीन के दोस्त रहे हैं। हरदीप पुरी की बेटी की कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा है- जैसे ही मैंने संसद में ये बात रखी तो स्पीकर ने फिर मुझे बोलने से रोक दिया। यानी नरेंद्र मोदी दोनों साइड से फंसे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अमीर होना ही नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी का ये डिजाइन गांधी जी के समय से ही है। जिस दिन हम अमीर पार्टी बन जाएंगे, उस दिन हम क्च्छ्वक्क हो जाएंगे। ये बात हमें लोकसभा चुनाव के दौरान समझ आई, जब हमारे सारे खाते फ्रीज कर दिए गए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए ज़्योंकि ये विचारधारा की पार्टी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी %साइकोलॉजिकली% खत्म हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि संविधान वो शक्ति है, जिसने सभी देशवासियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है- समानता और सज़्मान का अधिकार दिया है। हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करते रहेंगे।

राहुल ने कहा कि कांग्रेस एक गरीब पार्टी है, जबकि क्च्छ्वक्क अमीर पार्टी बन गई, ज़्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्च्छ्वक्क का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अडानी को सौंप दिया है। अमेरिका ने इसी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पकड़ लिया और अडानी पर केस कर दिया। यह केस अडानी पर नहीं, बल्कि क्च्छ्वक्क पर है। इसीलिए नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं, जो अमेरिका कह रहा है। नरेंद्र मोदी को %ज़्लैकमेल% किया जा रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पिछले चार महीने से रुकी हुई थी, ज़्योंकि सरकार कृषि सेज़्टर से समझौता नहीं करना चाहती थी। लेकिन संसद में मेरे भाषण के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन किया और ट्रेड डील के लिए हामी भर दी, जिसके बाद ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। जो डील पिछले चार महीने से रुकी हुई थी, नरेंद्र मोदी ने वो डील श्वश्चह्यह्लद्गद्धद्ध फाइल और अडानी के कारण 15 मिनट में फाइनल कर दी।

ग्लोबल क्राइसिस के बीच मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आश्वान, भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें

नयी दिल्ली १३/०३ (संवाददाता): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और भारत के पास पर्याप्त कच्चा तेल है। भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति की स्थिति को सुरक्षित बताते हुए, केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अफवाहें न फैलाने और झूठी बातें गढ़ने से बचने का आग्रह किया। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक ऊर्जा इतिहास में दुनिया ने कभी ऐसा संकट नहीं देखा है। भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति की स्थिति सुरक्षित है, और सुरक्षित मात्रा होर्मुज जलडमरूमध्य से मिलने वाली मात्रा से कहीं अधिक है।

पुरी ने कहा कि संकट से पहले, भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 45 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से होकर गुजरता था। प्रधानमंत्री के उत्कृष्ट राजनयिक प्रयासों और सद्भावना के कारण,

भारत ने उतनी मात्रा में कच्चा तेल सुरक्षित कर लिया है जितनी कि बाधित होर्मुज जलडमरूमध्य से उसी अवधि में मिल सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। कई मामलों में, वे 100त्न से भी अधिक क्षमता पर चल रही हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या ईंधन तेल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन, टर्बाइन ईंधन, केरोसिन और ईंधन तेल की उपलज़्धता पूरी तरह सुनिश्चित है।

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि संघर्ष शुरू होने से पहले कच्चे तेल के आयात में गैर-होर्मुज स्रोतों का हिस्सा 55त्न था, जो अब बढ़कर लगभग 70त्न हो गया है। भारत के स्रोत 2006 और 2007 में 27 देशों से बढ़कर 40 हो गए हैं। लगातार कई वर्षों तक अपनाई गई नीति के माध्यम से हासिल किए गए इस संरचनात्मक विविधीकरण ने हमें ऐसे विकल्प दिए हैं जो अन्य देशों के पास नहीं हैं। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। कई मामलों में, वे 100त्न से भी अधिक क्षमता पर चल रही हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ या ईंधन तेल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, विमानन ईंधन, टर्बाइन ईंधन, केरोसिन और ईंधन तेल की उपलज़्धता पूरी तरह सुनिश्चित है। देश भर के खुदरा स्टोरों में इन उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक है और इनकी आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों के माध्यम से लगभग प्रतिदिन बड़ी मात्रा में एलएनजी की खेप आ रही है। भारत के पास पर्याप्त गैस उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था है जिससे वह लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की स्थिति में भी इस स्थिति को बनाए रख सकता है। प्रत्येक घर और उद्योग के लिए बिजली उत्पादन पूरी तरह से सुरक्षित है... अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से खेप प्राप्त करके खरीद प्रक्रिया को सक्रिय रूप से विविधीकृत किया गया है।

विपक्ष के माइक ऑफ के आरोप पर स्पीकर ओम बिरला का पलटवार, कहा-मेरे पास कोई बटन नहीं है

नयी दिल्ली १३/०३ (संवाददाता): लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के माइक बंद करने के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि स्पीकर की कुर्सी पर ऐसा कोई बटन नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन नियमों से चलता है और जिसे बोलने की अनुमति दी जाती है, केवल उसी का माइक्रोफोन चालू रहता है। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान विफल होने के बाद पहली बार बोलते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि स्पीकर ने किसी भी सांसद के भाषण के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद किया था। उन्होंने इस दावे को भी नकार दिया कि कुछ सदस्यों, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों को, चर्चा के दौरान बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी।बिरला ने लोकसभा में अपने बयान में कहा कि कुछ सदस्यों ने यह मुद्दा भी उठाया कि विपक्षी सांसदों के माइक्रोफोन बंद कर दिए गए थे। मैंने यह बात पहले

भी कही है। कुर्सी पर माइक्रोफोन चालू या बंद करने का कोई बटन नहीं है। यहां तक ??कि विपक्षी सांसद भी इस कुर्सी पर बैठकर काम करते समय यह बात जानते हैं। उस समय जिसे भी बोलने की अनुमति दी जाती है, उसका माइक्रोफोन चालू रहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन का कोई भी सदस्य नियमों और कार्यवाही से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन नियमों को लागू करना स्पीकर का कर्तव्य है। सदन का कोई भी सदस्य सदन के नियमों और कार्यवाही से संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन नियमों को लागू करना मेरी जिज़्मेदारी और कर्तव्य है। सत्र के शेष समय के लिए कुछ सांसदों को निलंबित करने के अपने निर्णय के बारे में बात करते हुए, बिरला ने कहा कि उन्होंने हमेशा सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई सदस्य सदन की गरिमा पर हमला करता है, तो मुझे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। संसद में भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 105 के बारे में बोलते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि भाषण की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह सदन के नियमों और परंपराओं द्वारा नियंत्रित होती है। उन्होंने कहा कि सदन के एक सदस्य ने अनुच्छेद 105 के तहत संसद में भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया था। हालांकि हमें संसद में भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह सदन के नियमों और परंपराओं द्वारा नियंत्रित होती है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

लिविंग रूम को स्टाइलिश बना देंगे ये लैंप

घर में लिविंग रूम सबसे खास होता है। यह घर को वो खास हिस्सा है जहां पर आप मेहमनों का स्वागत कर सकते हैं और सारे दिन की थकावट भी इसी रूम में आराम करके उतर जाती है। इस खास जगह का इंटीरियर भी अगर शानदार हो तो यहां समय बिताने में बहुत मजा भी आता है। आजकल लोग घर के इंटीरियर को लेकर बहुत चूजी हो गए हैं। वह घर में हर चीज को स्टाइलिश तरीके से रखना पसंद करते हैं। पहले सिर्फ सोफे और कुर्सी को इंटीरियर का खास हिस्सा माना जाता था लेकिन अब इसमें वॉल डेकोरेशन,शो पीस,प्लांटस के साथ-साथ लैंप को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। घर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है स्टाइलिश चेयर और सोफे के साथ लैंप भी शानदार हो। इससे घर को रॉयल लुक भी मिलती है। आजकल बाजार में बहुत तरह के लैंप आसानी से मिल जाते हैं,जिसे आप अपने लिविंग रूम का खास हिस्सा बना सकते हैं।

इस तरह के लैंप टेबल पर नहीं बल्कि फ्लोर पर रखने वाले होते हैं। जो सिंपल से सोफा और चेयर सैट को भी स्टाइलिश लुक देता है। आप अपने फर्नीचर या फिर रूम के कलर के हिसाब से मैच करके भी रख सकते हैं। रूम को लग्जरी लुक देना चाहते हैं को इस तरह के लैंप आपके लिए बैस्ट हैं। कम फर्नीचर के साथ भी यह कमरे की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं।

मॉडर्न स्टाइल से घर को सजाना है तो इस तरह के लैंप बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी लैंथ फ्लोर से बहुत ऊंची होती हैं।

इस तरह बनाए पुराने स्मार्टफोन से सीसीटीवी कैमेरा

अक्सर लोग नया फोन लेते समय लोग आपने पुराने स्मार्टफोन को फैंक देते है। अगर आपका फोन ठीक से काम करता हो तो आप उसे बेच देते है या फिर उसे घर पर ऐसे ही पड़ा रहने देते है लेकिन अब आप उसे बेचने की बजाए घर के लिए सीसीटीवी कैसरा बना सकते है। इससे आपको पुराना फोन कम दाम पर बेचना भी नहीं पड़ेगा और वो आपके काम भी आ जाएगा।

ऑफिस या घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए काफी पैसे खर्च कर देते है लेकिन मंहगा होन के कारण कई लोग इसे खरीद नहीं पाते है। पुराने फोन की मदद से आप घर के लिए बिना किसी मदद के सीसीटीवी कैसरा बना सकते है। इससे आपके पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेगें और आपके घर के लिए सीसीटीवी कैसरा भी बन जाएगा। स्मार्टफोन से घर के लिए सीसीटीवी कैसरा बनाने के लिए आप उसमें सीसीटीवी ऐप को डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में सीसीटीवी सर्च करने पर आपको कई ऐप मिल जाएंगे।

डाउनलोड होने के बाद यूजर अपनी गूगल अकाउंट की डिटेल को ऐप में डाल दें। डिटेल देने के बाद आपको इसमें कैमरा और व्यूअर नजर आ जाएगा। नेक्सट करने के बाद कैमरे के स्क्रीन व्यू को सिलेक्ट करें। इससे आपका स्मार्टफोन ब्लैंक या फिर विजिबल मोड पर आ जाएगा। अब आप इसे घर की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते है। आप इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते है।

जिसे आप बाद में देख सकते है। अगर आपका फोन चार्ज नहीं होगा तो आप रिकॉर्डिंग को देख नहीं पाएगें। इसलिए समय-समय पर अपने फोन को चेक करते रहें और बैटरी लो होने पर इसे चार्ज कर लें। इसे आप अपने टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते है।

बेकार रस्सियों से बनाएं घर के लिए क्रिएटिव

घर में बहुत सी बेकार चीजें होती है, जिन्हें आप इस्तेमाल करने की बजाए फैंक देती है। उसी तरह घर में पड़ी बेकार रस्सी को भी आप बिना उसके फायदे जाने फैंक देती है। घर में पड़ी बेकार रस्सी का इस्तेमाल आप अपने घर के लिए टोकरी बना सकती है। इस टोकरी का इस्तेमाल आप किचन से लेकर मेकअप का सामान रखने के लिए कर सकती है। आइए जानते है कि किस तरह से आप बेकार रस्सीयों से अपने घर की सजावट कर सकती है।

जरूरी सामान

रस्सी से कलाकृति बनाने के लिए आपको बेकार रस्सी, प्लास्टिक का टब (किसी भी साइज का), ग्लू, कलर चाहिएं होंगे।

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले तो टब को प्लास्टिक बैग में लपेट दें। इसके बाद इसके ग्लू से रस्सी को चारों तरफ लपेटते हुए चिपका दें।

2. अच्छी तरह से चारों तरफ रस्सी चिपकाने के बाद टब के सखने के लिए रख दें। सूखने के बाद आप टब को धीरे-धीरे रस्सीयों के अंदर से निकाल लें।

3. टब निकालने के बाद इसे थोड़ी देर और सूखने के लिए रख दें। जब टब अच्छी तरह से सूख जाएं तो इसपर आप अपनी पंसद से कोई भी कलर कर दें। इसके अलावा इस आप अपनी पसंद से फूल भी लगा सकती है।

4. इस सुंदर टोकरी में आप किचन या घर का कोई भी सामान रख सकती है। इसके अलावा इस तरीके से छोटी टोकरी बना कर आप इसमें अपना मेकअप का समान भी रख सकती है।

5. टोकरी बनाने के अलावा इससे आप घर की बाकी चीजे जैसे फोटो फ्रेम, मिरर या फिर कोई भी सामान डेकोरेट कर सकती है। इसकी टोकरी बना कर आप उसमें फूलों को लगा कर गार्डनिंग भी कर सकती है।

विवाह कार्ड में भी लोग अपनाते हैं वास्तु नियम

हर लड़का और लड़की का सपना होता है कि वह शादी करें। आजकल के लोग शादी के हर फकंशन को पूरी तरह से एज्वाय भी करते है। शादी से जुड़ी हर रस्म को लोह बहुत अरमानों के साथ निभाते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी काम की शुरूवात अच्छे से हो तो सारी जिंदगी अच्छे से गुजरती है। इसी तरह शादी की शुरूवात भी न्योते यानि मेहमानों को बांटे जाने वाले कार्ड से होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये निमंत्रण पत्र भी वास्तु के हिसाब से ही होने चाहिए। इसका पूरा असर वर-वधू की जिंदगी पर पड़ता है।

वास्तु के अनुसार कार्ड

शादी के कार्ड का आकार और रंग भी साकारात्मक और नाकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। कार्ड बनवाने से पहले वास्तु के हिसाब से ही कार्ड के अक्षरों का रंग और स्टाइल का चुनाव करें।

कार्ड का आकार

कार्ड का आकार लाइफ पर भी असर डालता है। टेढ़े-मेढ़े आकार के कार्ड साकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं करते। वर्गाकार आकार के कार्ड सबसे बेहतर हैं।

काले अक्षरों में न लिखाएं नाम

शादी के कार्ड पर वर-वधू का नाम काले अक्षरों में नही लिखवाना चाहिए। इससे अशुभ घटनाएं घटने का डर रहता है।

रंगों का चुनाव

शादी के निमत्रंण पत्र में रंगों को भी खास खयाल भी रखना चाहिए। बैंगनी,ऑफ व्हाइट,ग्रे और काले रंगों का इस्तेमाल कार्ड में न करें। लाल,पीला और हरा रंग शुभ संकेत है और यह साकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है।

न करें तस्वीरों का इस्तेमाल

आजकल लोग शादी के कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की तस्वीरें लग देते हैं। इन कार्ड को लोग बाद में फैंक देते हैं जो शुभ संकेत नहीं है। इससे दोनों की सेहत और खुशियों पर बुरा असर पड़ता है।

कमल का फूल

कमल के फूल को बहुत शुभ माना जाता है। कार्ड किसी न किसी रूप में कमल की आकृति जरूर छपवाएं। इससे जिंदगी में खुशियां आती हैं।

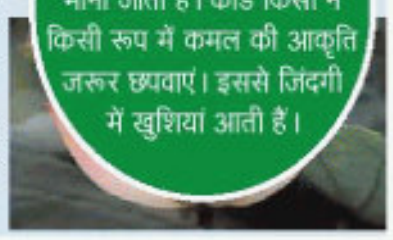

पथरी से बचना चाहते हैं तो, इन चीजों से बना लें दूरी

रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने खान-पान का ध्यान रख पाते हैं। इसी वजह से वे कई गंभीर बीमारियों को न्यौता दे रहे हैं। ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिन्हें खाने से आप पथरी का शिकार बन रहे हैं इसलिए इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए।

- पालक में ऑक्सलेट होता है जो कैल्शियम के मिलकर उसे बांध लेता है और यूरीन में नहीं जाने देता। इसलिए अगर पथरी से बचना चाहते हैं तो पालक का कम सेवन किया करें।
- टमाटर के बीजों में ऑक्सलेट भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए हमेशा टमाटर के बीज निकालकर ही इसका इस्तेमाल करें।
- सी फूड्स में प्यूरीन नाम का तत्व मिला होता है। इसकी वजह से शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड बनने लगता है। इसलिए इनका सेवन कम किया करें । क्योंकि यूरिक एसिड से पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है।
- सोडियम की ज्यादा मात्रा लेने से भी पथरी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पथरी से दूर रहने के लिए नमकीन चीजों का सेवन कम से कम करें।
- पथरी की परेशानी से दूर रहने के लिए सोडा कम से कम पिएं। दरअसल, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है । जिससे स्टोन होने का खतरा बढ़ता है।

सोराइसिस से बचाती है हल्दी, एंटी सेप्टिक गुण

सोराइसिस त्वचा का ऐसा गंभीर रोग है, जिसमें त्वचा की पर्त बदसूरत व बदरंग होने लगती है। यह रोग अधिकतर खून की खराबी से उत्पन्न होते हैं। सोराइसिस होने का एक मुख्य कारण शरीर में अम्ल व क्षार का असंतुलन और इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के कारण होता है। यह रोग अधिकतर खून की खराबी से उत्पन्न होते हैं। सोराइसिस में हल्दी का प्रयोग फायदेमंद होता है। हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक गुण सोराइसिस की बीमारी से बचाव करते है।

सोराइसिस का इलाज

कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक गुण होते हैं। इसमें इंफेक्शन से लड़ने के गुण भी पाए जाते हैं। इसमें सोराइसिस जैसे त्वचा संबंधी रोगों से बचाव के गुण होते हैं। हल्दी में छः प्रतिशत एक हरे भूरे रंग का कर्पूर की सी गन्ध वाला उड़नशील तेल पाया जाता है तथा इसमें करक्यूमिन नामक रंजक द्रव्य होता है। इसके अतिरिक्त इसमें स्टार्च एवं एल्ब्यूमिनॉयड्ड पाए जाते हैं।

हल्दी का रक्त विकार एवं त्वचा रोगों की अन्य औषधियों के साथ उपयोग होता है। हल्दी पूरी तरह से एंटी बायोटिक होती है। इसलिए, इसके सेवन से आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बीमारी होने की संभावना कम होती है। हल्दी खून को साफ करती है और ऊर्जा को निर्मल बनाती है। हल्दी सिर्फ आपके शरीर पर ही काम नहीं करती, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। यह शरीर, खून और ऊर्जा तंत्र की सफाई करती है।

हल्दी प्रयोग करने का तरीका

आधा किलो हल्दी पीसकर चार लीटर पानी में घोलकर उबालें और ठण्डा करके इसमें दो सौ ग्राम शहद मिला दें। इस मिश्रण को किसी शीशे के बर्तन में दो सप्ताह तक रखा रहने दें, अब इसको छानकर किसी साफ बोतल में भरकर रख दें। खाना खाने के बाद इस आसव को दस या पन्द्रह ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इस आसव को पीने से रक्त साफ हो जाता है। शहद युक्त हल्के गुनगुने पानी के साथ नीम और हल्दी का सेवन एक शानदार तरीके से कॉस्मेटीय स्तर पर सफाई कर उन्हें खोलने का काम करता है, जिससे वे आपके भीतर अच्छी तरह से ऊर्जा अवशोषित कर सकें। यह शरीर, खून और ऊर्जा तंत्र की सफाई करती है। बाहरी सफाई के लिए अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और इस पानी से नहाएं। आप पाएंगे कि आपका शरीर दमकने लगेगा। दूध में हल्दी चूर्ण मिलाकर सुबह शाम लेना चाहिए। रोज के अपने खाने में हल्दी को शामिल करें। हल्दी विसंक्रमकारी गुणों से भरपूर है । परंतु कुछ लोगों पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। जिन लोगों को हल्दी से एलर्जी है उन्हें पेट में दर्द या डायरिया जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं।

कलिंग समाचार

संपादकीय

शनिवार 14 मार्च 2026

मोदी के हाथ में त्रिशूल और डमरू

गले में भगवा गमछा, माथे पर त्रिपुंड और हाथों में भगवान शिव की तरह त्रिशूल और डमरू पकड़े हुए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नया अवतार सामने आया है। अलग-अलग विचारधारा और कार्यशैली के प्रधानमंत्री देश ने देखे हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री को देश देख रहा है, जिनकी वक्त-वक्त पर बदलती वेशभूषा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की याद दिलाती है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी कोई भी काम अकारण नहीं करते। इस बार हिंदुत्व का जयघोष करने वाली मुद्रा उन्होंने सोमनाथ में 8 से 11 जनवरी तक आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए धारण की। इस उत्सव को भव्य बनाने में गुजरात की भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि इसके गहरे राजनैतिक निहितार्थ भी हैं। एक हजार साल पहले1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला हुआ था। उसी याद में यह उत्सव मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चन्द्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। लोककथाओं के अनुसार यहीं श्रीकृष्ण ने देहत्याग किया था। यह ऐतिहासिक मंदिर अब भाजपा के लिए राजनैतिक महत्व का भी बन गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के अनुसार, यह उत्सव विनाश को याद करते हुए नहीं बल्कि आस्था, सांस्कृतिक आत्मस मान और पुनर्जन्म की भावना के स मान के रूप में मनाया जा रहा है। दरअसल प्राचीन सोमनाथ मंदिर में कई गांवों का चढ़ावा आता था, जिससे यहां सोने, चांदी, बड़ी सं या में मोतियों और अनमोल रत्नों समेत बड़ी धनसंपदा सदियों से जमा थी और इस वजह से विदेशी हमलावर इसे लूटना चाहते थे। महमूद गजनी ने 1026 में जब भारत पर एक और आक्रमण किया तो उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम का शासन था, महमूद गजनी ने तभी सोमनाथ पर पहला आक्रमण किया था। इसके बाद कई और शासकों और आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर हमले किए और इसकी धन संपदा को लूटा। मध्ययुग का वह दौर ऐसा ही था, जिसमें राज्य और शक्ति बढ़ाने के लिए शासक खुलेआम लूटपाट करते थे। अभी अमेरिका इसी तरह के काम कर रहा है, बस इसमें लोकतंत्र का आवरण ओढ़ लिया है और सीधे-सीधे गैर धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। खैर, सोमनाथ पर कम से कम 16 बार आक्रमण और देश के दूसरे हिंदू धर्मस्थानों पर हुए आक्रमण के बावजूद देश से न हिंदू धर्म खत्म हुआ, न हिंदुओं के अस्तित्व पर कोई खतरा आया। लेकिन मोदीराज में आस्था के पुनर्जन्म के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। सोमनाथ पर भाजपा पहले भी सफल दांव खेल चुकी है। दिसंबर 1989 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने पहली बार अपने चुनावी घोषणापत्र में राम मंदिर (अयोध्या) निर्माण के मुद्दे को शामिल किया था। तब उसकी लोकसभा सीटें बढ़ीं, फिर 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की, जिसके बाद भारत में वही धार्मिक विभेद की खाई गहरी होनी शुरु हुई, जो भाजपा की सत्ता के लिए जरूरी थी। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। फिर 1996 में भाजपा को केंद्र की सत्ता में आने का मौका पहली बार मिला। और अब नरेन्द्र मोदी के आने के बाद तो 12 सालों से भाजपा के पास सत्ता है। ध्यान रहे कि आडवाणी की रथयात्रा में गुजरात में नरेन्द्र मोदी को बड़ी जि मेदारी दी गई थी, जिसे मोदी ने सफलतापूर्वक निभाया। सवाल भाजपा को सत्ता में लाने का था, तो नरेन्द्र मोदी ने पूरी तैयारी से अपनी जि मेदारी निभाई। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद मोदी लगातार अपने पद की गरिमा निभाने में नाकाम दिख रहे हैं। इंदौर में कई लोग दूषित पेयजल से मर गए, मोदी ने उफ तक नहीं की। दिल्ली से लेकर कई शहरों में हवा जानलेवा बनी हुई है। उन्नाव की पीड़िता इंसाफ के लिए लड़ती रही, मोदी चुपचाप देखते रहे। अभी अंकिता भंडारी मामले में लोगों ने आक्रोश न दिखाया होता तो भाजपा सरकार बेफिक्र बैठी रहती। उत्तरप्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं।

मुस्लिम सावधान:ओवैसी बंगाल में हिजाबी मुख्यमंत्री का शिगूफा छेड़ सकते हैं!

शकील अख्तर

देश में जहां अभी केन्द्र सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री तक नहीं है वहां हिजाबी महिला के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाने की बात करना सिवाय जज्बात भड़काने के और क्या है? मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के बहुत सारे काम होना है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही बनेगी लेकिन नौकरी पाकर बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं मजबूत होंगी। महिला शिक्षा महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने पर ओवैसी कभी बात नहीं करते हैं। असदउद्दीन ओवैसी को बड़ा बैरिस्टर कहकर उनका महिमामंडन किया जाता है। लेकिन एक सामान्य वकील भी जानता है कि उन्हें किसी ऐसे तर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो उसके क्लाइंट के लिए ही उल्टा पड़ सकता हो। एक बार नहीं दूसरी बार फिर ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी।

भारत का प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। संविधान कहता है। मगर अभी तक कोई दलित भी नहीं बन सका है। अपने व्यक्तिगत करिश्मे के दम पर मायावती को यह मौका मिल सकता था। मगर डर की राजनीति की वजह से उन्होंने यह गंवा दिया। बड़ी पार्टियों में से भाजपा अपनी मनुवादी सोच के कारण कभी किसी दलित को यह मौका नहीं दे सकती है। उसकी तो आरक्षण और उस संविधान को भी जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है खत्म करने की मंशा है। मगर मौका नहीं मिल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी चार सौ पार मांगे थे मगर अभी थोड़ा होश में बची जनता और विपक्ष के एकजुट होकर चुनाव लड़ने की वजह से उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। वहां दलित प्रधानमंत्री की बात कोई सोच भी नहीं सकता। संघ की और बीजेपी की पूरी राजनीति सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरोध में है। वापस पुरानी व्यवस्था बनाना। जिसे वह समरसता कहती है। यह शब्द संघ का ही गढ़ा हुआ है। मगर जानकारी के अभाव में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेता, लेखक पत्रकार भी इस शब्द का उपयोग सामाजिक न्याय के संदर्भ में करते रहते हैं। जबकि यह शब्द कहता है कि दलित पिछड़ों को स्थापित समाज के साथ समरस रहना चाहिए। मतलब उनके अनुसार बनी हुई सामाजिक व्यवस्था में।

दलित नेता रामदास अठावले यह जानते हैं। मोदी के साथ रहने के बावजूद उन्होंने पत्र लिखकर उनसे कहा था कि सरकारी कागजों में सामाजिक न्याय के बदले इस शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसे बंद होना चाहिए। जाहिर है कि उनकी इस बात को किसी को सुनना नहीं था। मगर संतोष की बात है कि कुछ दलित नेता संघ की इन बारीक कारगुजारियों को समझते हैं। कुछ कर नहीं पाएं वह अलग बात है। ज़्यादा जानें बॉलीवुड समाचार खेल उपकरण बजट 2019 युवा मनोरंजन विविध समाचार हिंदी समाचार ऐप सदस्यता राजनीति समाचार बॉलीवुड समाचार पत्रिका साक्षात्कार कौशल प्रशिक्षण समाचार सदस्यता तो दलित जिसे वे हिन्दुत्ववादी राजनीति में शामिल मानते हैं उसे वे देश के सर्वोच्च पद की लिए स्वीकार नहीं कर सकते तो मुस्लिम का नाम जिसके खिलाफ उनकी पूरी राजनीति है उसकी हिजाबी महिला का नाम आना तो उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए और फायदेमंद ही है।

ओवैसी यह काम कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि बीजेपी की हिन्दू-मुस्लिम राजनीति कमजोर पड़ गई है। तो उसे वापस मजबूत करने के लिए ओवैसी ने अपने इस बयान को फिर दोहरा दिया। इससे पहले वे कर्नाटक में इस विषय पर हुए विवाद के बाद यही बात कि हिजाबी लड़की एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी कह चुके थे। ओवैसी मुस्लिम की राजनीति करते हैं। और इस के लिए वे सबसे बड़ा मुद्दा यह उठाते हैं कि मुस्लिम का नेता मुस्लिम ही हो सकता है। वे मुस्लिम कयादत की बात करते हैं। यह बात तो बीजेपी को बहुत सूट करती है। 15- 16 प्रतिशत मुस्लिम का नेता मुस्लिम तो बाकी हिन्दुओं का नेता हिन्दू। तो उनकी मुस्लिम कयादत की राजनीति में देश का बहुसं यक गैर मुस्लिम हिजाबी महिला प्रधानमंत्री को कैसे स्वीकार कर लेगा?

देश में जहां अभी केन्द्र सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री तक नहीं है वहां हिजाबी महिला के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाने की बात करना सिवाय जज्बात भड़काने के और क्या है? मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के बहुत सारे काम होना है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही बनेगी लेकिन नौकरी पाकर बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं मजबूत होंगी। महिला शिक्षा महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने पर ओवैसी कभी बात नहीं करते हैं।

बस बैरिस्टर साहब हिजाबी महिला के प्रधानमंत्री बनने की बात हर उस समय दोहरा देते हैं जब बीजेपी को सा प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए उसकी जरूरत होती है। यह बैरिस्टर विपक्षी को अपने क्लाइंट (मुस्लिम जिसके वे कायद,नेता होने का दावा करते हैं) पर और ज्यादा हमले करने का मौका मुहैया करवाते हैं। बंगाल में चुनाव हैं। बीजेपी को मुस्लिम वोट काटने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी ओवैसी ही हो सकते हैं। इस तरह के जज्बात भड़काकर वे मुस्लिम वोट काटते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है।

अभी बिहार में सबसे देख लिया। ओवैसी ने बीजेपी के सा प्रादायिक ध्रुवीकरण का साथ देकर उसके अब तक के सर्वाधिक 89 विधायकों को चुनाव जितवा दिया और खुद भी सबसे ज्यादा 5 मुस्लिम विधायक जितवा लिए। लेकिन नुकसान क्या हुआ? 243 सीटों में से मुस्लिम विधायकों की सं या केवल 11 रह गई। जबकि पिछली बार 2020 में 19 थी। और 2015 में 24। ओवैसी की खुद की सीटें आ जाती हैं और बाकी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की सीटें भी कम हो जाती हैं और उनसे लड़ने वाले मुस्लिम प्रत्याशी भी हार जाते हैं। ज़्यादा जानें खेल उपकरण संपादकीय लेख युवा मनोरंजन साक्षात्कार संग्रह विविध समाचार बजट 2019 मनोरंजन पत्रिका प्रमुख समाचार हिंदी समाचार ऐप सदस्यता ई-पेपर सदस्यता बंगाल में इस बार बीजेपी हर दांव आजमा रही है। ममता बनर्जी के लिए हर फ्रंट पर मुश्किलें खड़ी कर रही है। ईडी की एंट्री करवा दी है। एसआईआर चल ही रहा है। और धार्मिक विभाजन के लिए वहां बाबरी मस्जिद बनवाने और हिजाबी महिला के प्रधानमंत्री बनने की जज्बाती राजनीति की शुरूआत करवा दी गई है। बिहार में तो केवल 18 प्रतिशत ही मुस्लिम वोट थे। बंगाल में इससे लगभग दो गुने हैं। वहां इस समय 44 मुस्लिम विधायक हैं। मगर इससे बहुत ज्यादा सं या में वहां मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष दलों को जिनमें इस समय वहां टीएमसी ही प्रमुख है, चुनाव जितवाता है। हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और ओवैसी जो अभी तो हिजाबी मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं चुनाव आने तक कोई आश्चर्य नहीं करना कि वे बंगाल में हिजाबी मु यमंत्री की बात न करने लगें।

प्रधानमंत्री दूर की चीज है। बंगाल में महिला मु यमंत्री हैं तो यहां हिजाबी मु यमंत्री का नारा ज्यादा चलेगा! सावधान ममता को या दूसरे धर्मनिरपेक्ष दलों को नहीं रहना है। वे तो अपने सिद्धांतों पर रहेंगे होशियार मुस्लिम को रहना होगा। जिन्ना की इसी तरह की राजनीति ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जो पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया वह पूरी तरह एक फेल्ड स्टेट (असफल राष्ट्र) में तबदील हो चुका है। तरक्की के मामले में वह भारत के मुकाबले कहीं नहीं है। भारत का मुसलमान हमेशा से धर्मनिरपेक्ष नेताओं को ही अपना नेता मानता रहा है। पहले नेहरू को माना फिर मुलायम, लालू, ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ भी गया। लेकिन अब ओवैसी नया शिगुफा लाए हैं। मुसलमानों को अपनी कयादत खड़ी करना होगी। 15-16 प्रतिशत आबादी अपनी कयादत खड़ी करके क्या करेगी? वही हाल होगा जो अभी बिहार में हुआ। न कयादत खड़ी होगी न दूसरे धर्मनिरपेक्ष दल जीत पाएंगे। न खुदा ही मिला न विसाले सनम वाली हालत हो जाएगी। बंगाल के साथ अभी असम और केरल में भी चुनाव हैं। वहां भी बंगाल की तरह मुस्लिम विधायकों की सं या अच्छी खासी है। दोनों जगह 32-32 विधायक हैं। इनके साथ तमिलनाडु में भी चुनाव हैं वहां 6 हैं। और पुडुचेरी में एक। हवा सब जगह एक साथ चलेगी। मीडिया इसे और बढ़ाएगा। रोकना केवल मुस्लिम के हाथ में है। जज्बातों में नहीं बहना। जो इशु बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा उसके हिन्दू भाइयों के हैं वही उसके भी। हिजाबी प्रधानमंत्री और हिजाबी मु यमंत्री कोई इशु नहीं हैं। यह जबर्दस्ती बनाया जा रहा इशु है। भावनाओं को भड़काने के लिए। ज़्यादा जानें संपादकीय लेख ताज़ा समाचार मु य शीर्षक ताज़ा खबरें अपडेट प्रादेशिक समाचार राजनीति समाचार हिंदी भाषा शिक्षण डिजिटल मार्केटिंग सेवाएँ बजट संबंधित वित्तीय सेवाएँ साक्षात्कार संग्रह मुस्लिम को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा की हिन्दू-मुस्लिम राजनीति को अब हिन्दू नकार रहा है। बहुत नुकसान उठा लिया उसने। सरकारी नौकरी खत्म हो गई। उसके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए अब दांव मुस्लिम पर लगाया जा रहा है कि वह जज्बाती इशु को हवा देगा ताकि फिर हिन्दुओं को भी उसी लाइन पर वापस लाया जाए। सा प्रदायिक राजनीति खत्म होना हिन्दू मुसलमान दोनों के हित में है।

देश के लिए फायदेमंद है चाइल्ड केयर में निवेश करना

डॉ. पवित्र मोहन

एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की पालना योजना के तहत परिकल्पित राज्य प्रायोजित डे-केयर सेंटर में बड़ी संभावनाएं हैं लेकिन वे वर्तमान में महत्वाकांक्षा न होने और कम बजटीय आवंटन से विवश होने से ग्रस्त हैं। मजबूत परिवारों को मजबूत सहायक संरचनाओं की आवश्यकता होगी। समाज और राज्य की जि मेदारी है कि वे इन्हें स मान के साथ प्रदान करें। फ़ैमिली गेम न्यूयार्क में मेयर का चुनाव जीतने वाले जोहरान ममदानी की जीत का एक बड़ा कारण शहर के सभी बच्चों के लिए राज्य प्रायोजित चाइल्ड केयर की गारंटी देना था। लोक कल्याण पर खर्च न करने की नीति रखने वाले, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रू प के समय और अमेरिका में दूर-दक्षिणपंथ की नई और यहां तक कि अंधी दिशा में जा रहे देश में यह एक साहसिक वादा था। ममदानी की जीत इंगित करती है कि अमेरिकी मतदाता साहसिक विचारों के साथ काम करते हुए समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। भारत के संदर्भ में बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक बड़ी चुनौती को देखते हुए इस विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है कि कैसे और क्यों बच्चों पर केंद्रित जमीनी स्तर के विकास का एजेंडा विभिन्न दलों के राजनीतिक एजेंडे में वरीयता प्राप्त कर सकता है।

बच्चों को हर जगह एक सुरक्षित, सहायक व पोषण करने वाले वातावरण की आवश्यकता होती है। आधुनिक दुनिया और इसकी अर्थव्यवस्था ने सामाजिक-आर्थिक स्तर पर बच्चों की देखभाल करने के लिए परिवारों की क्षमता को सीमित कर दिया है। छोटे परिवार के आकार, माता-पिता दोनों को घर से बाहर काम करने की आवश्यकता, लंबे समय तक काम के घंटे, लोगों को काम के लिए बाहर जाने की जरूरत; इन सभी मुद्दों ने अपने बच्चों की देखभाल करने की परिवारों की क्षमता को कम कर दिया है।

हालांकि अमीर परिवार निजी चाइल्ड केयर का खर्च उठा सकते हैं और उनके बच्चे घर पर या संस्थानों में बढ़ते रहते हैं, परन्तु गरीब परिवारों में बच्चे समुचित चाइल्ड केयर के बिना बढ़ते हैं जो अक्सर उनकी वृद्धि, विकास और भावनात्मक क्षमता को अत्यंत सीमित कर देते हैं। आमतौर पर किसी भी देखभाल करने वाले की अनुपस्थिति में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से भी समझौता किया जाता है। यह देखा गया है कि ग्रामीण भारत, विशेष रूप से ग्रामीण राजस्थान के कई हिस्सों में पुरुष श्रम-रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं जबकि महिलाएं और बच्चे अक्सर पीछे रह जाते हैं। महिलाएं जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने, पानी लाने, खेतों में काम करने और बुजुर्गों की देखभाल करने का काम करती हैं। उनके पास खुद की या अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए समय नहीं होता। अधिकतर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे खुद अपनी देखभाल करते हैं या उनका कोई बड़ा भाई-बहन उनकी देखभाल करता है जो अक्सर खुद ही एक छोटा बच्चा होता है। कभी-कभी दादा-दादी को बच्चों की देख-भाल करने का जि मा दिया जाता है पर ज्यादातर मामलों में वे स्वयं अपनी शारीरिक स्थितियों के कारण असमर्थ होते हैं। फलतः कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कभी बच्चे कुओं में गिर जाते हैं या जानवरों द्वारा रौंद दिए जाते हैं अथवा अकेलेपन का शिकार हो कर निष्क्रिय पड़े रहते हैं।

राजस्थान की कई बस्तियों में जहां डे-केयर सेंटर चलाये हैं, उनमें देखा गया है कि ऐसे केंद्रों में रखे गए अधिकांश बच्चे अच्छी तरह से विकसित होते हैं और स्कूलों में उन बच्चों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिन्हें खुद के हाल पर छोड़ दिया जाता है। उनकी माताओं ने यह भी बताया कि जब वे काम के लिए जाती हैं तो अपने बच्चों की भलाई के बारे में उन्हें बहुत कम चिंता रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे खुद के आराम के लिए कुछ समय भी निकाल लेती हैं। शहरी अहमदाबाद में कई प्रवासी परिवार निर्माण स्थलों पर काम करते हैं जहां बच्चों को अक्सर इधर-उधर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे उन्हें चोट लगने, उनके उपेक्षित रह जाने और कुपोषण का बहुत खतरा होता है। इन स्थलों पर गैर-सरकारी संगठनों और नियोक्ताओं द्वारा प्रबंधित डे-केयर सेंटर इन परिवारों के बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और पोषण प्रदान करते हैं।

इन स्थितियों में बाल देख-भाल सीमित परिस्थितियों में की जाती है जो सरकार की मदद के बिना संचालित होती है और वह एक अधिकार नहीं होता। यह देखते हुए कि विकास के लिए बच्चों के प्रारंभिक वर्ष मूलभूत हैं और परिणामों को आजीवन आकार देते हैं, न्यूनतम निवेश से होने वाले भारी लाभों को देखते हुए और अधिक क्षेत्रों तथा राज्यों में बाल देख-भाल मॉडल का विस्तार करने की आवश्यकता है। इस बारे में किए गये कई अध्ययन इसका समर्थन करते हैं। जर्नल ऑफ ग्लोबल हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार नि न और मध्यम आय वाले देशों में 0-3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए केंद्र-आधारित चाइल्ड केयर पर अध्ययनों की एक प्रणालीगत समीक्षा बच्चों के विकास, पोषण और विकास मेट्रिक्स में सकारात्मक परिणामों से जुड़ी है। 2011 की एक लैंसेट समीक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चूंकि बच्चों का विकास हो रहा होता है तो बढ़ते केंद्र-आधारित प्रारंभिक शिक्षण कार्यक्रम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, स्कूल की तैयारी में सुधार करते हैं और मजबूत शैक्षणिक प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। हाशिए में रहने वाले बच्चों के लिए ये लाभ अधिक गहन होते हैं। वैश्विक साक्ष्य से पता चलता है कि संज्ञानात्मक कामकाज और सामाजिक-भावनात्मक कौशल का निर्माण बेहतर शिक्षा, रोजगार तथा वयस्क होने पर कमाई में बदल जाता है। यह गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने में मददगार होता है। जमैका से एक ऐतिहासिक अध्ययन (गर्टलर, पॉल, एट अल %लेबर मार्केट रिटर्न्स टू एन अर्ली चाईल्डहुड स्टिमुलेशन इंटरवेन्शन इन जमैका%, साईस- 2014) ने पाया कि जिन बच्चों को पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, उन्होंने 20 साल बाद उन लोगों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक आय अर्जित की जिन्हें ऐसे अवसर और सुविधाएं नहीं मिली थीं। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए अकाट्य सबूत हैं कि कम और मध्यम आय वाले देशों में भी बड़ी सं या में माताओं को काम करने में सक्षम बनाने में चाइल्ड केयर की उपलब्धता किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे-जैसे अधिक सं या में माताएं कार्यबल में शामिल होती हैं, समग्र रोजगार दर बढ़ती है। इकानॉमिस्ट इ पैक्ट के चाइल्ड केयर डिविडेंड इनिशिएटिव (%ब्रिजिंग द एक्सेस गैप% क्वांटिफाइंग द इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन चाइल्ड केयर%) द्वारा किए शोध का अनुमान है कि चाइल्ड केयर सेवाओं तक पहुंच गुणक प्रभाव के माध्यम से हर साल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 1 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि नि न और मध्यम आय वाले देशों में कार्यबल में माताओं की कम भागीदारी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। महिलाओं के लिए यह कीमत व्यक्तिगत और वित्तीय दोनों हैं। यह न केवल कैरियर के विकास को धीमा और कमाई को कम करता है बल्कि उनकी स्वतंत्रता तथा काम देने वाली एजेंसी की क्षमता को भी कम करता है। कम मातृ श्रम शक्ति भागीदारी दर के कारण घरेलू आय नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास कम होता है। द इकानॉमिस्ट की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अपर्याप्त चाइल्ड केयर कितना महंगा हो सकता है- नाइजीरिया में लगभग पांच में से एक बच्चा स्कूल जाने की उम्र से कम का है और अधिकांश छोटे बच्चों की देखभाल घर पर की जाती है। वहां 2022 में महिलाओं की काम करने की सीमित क्षमता के कारण देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.09 प्रतिशत आय का नुकसान हुआ। चाइल्ड केयर उद्योग में सृजित नौकरियों के कारण आर्थिक लाभ भी उत्पन्न होते हैं।

विविध समाचार

पंजाब : सीएम भगवंत मान ने मोहाली में ९०० से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए

मोहाली १३/०३ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को मोहाली में विभिन्न विभागों के 916 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी नव–नियुक्त उम्मीदवारों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पंजाब और पंजाबियों की सेवा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य सरकार द्वारा बिना रिश्वत और बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और 'मिशन रोजगार' के तहत यह प्रक्रिया आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब उम्मीदवारों को केवल परीक्षा देनी होती है, उसके बाद परिणाम और नियुक्ति पत्र सरकार स्वयं भेजती है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी है। मुख्यमंत्री

ने कहा कि 2022 में झाड़ू का बटन दबाकर जनता सरकार में भागीदार बनी, और उसी फैसले से आज शिक्षा, रोजगार और विकास की रोशनी पूरे पंजाब में फैल रही है, जबकि पिछली सरकारों के दौर में प्रदेश को सिर्फ अंधकार मिला। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने सरकार द्वारा किए गए जन–हितैषी कार्यों की सराहना करने के बजाय हमेशा कमियां ही निकाली हैं। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ काम पर है। पंजाब को दोबारा सही राह पर लाने के लिए लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हमें विरोधियों की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमें शहीदों के सपनों की आजादी को साकार करना है, तो हमें भी आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शहीदों के सपनों की आजादी को हकीकत में बदलने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज मोहाली में विभिन्न विभागों के 916 नौजवान लड़के–लड़कियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सभी को पूरी तन्मयता और ईमानदारी से पंजाब–पंजाबियों की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं दी। अब तक 63 हजार 943 युवाओं को बिना रिश्वत और बिना सिफारिश सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में भी 'मिशन रोजगार' के तहत इसी तरह युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र सौंपने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आम्बेडकर जी के नाम पर बनाए गए पोर्टल में जवाबदेही तय की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस योजना को स्कैम ना बना सके।

यदि कोई भी कॉलेज फर्जी दाखिला दिखाकर स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना की सुविधा सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। अब राज्य का कोई भी परिवार इलाज से वंचित नहीं रहेगा।

कनाडा में पंजाबी दंपती की मौत, घर में खून से लथपथ मिले शव, एक आरोपी हिरासत में

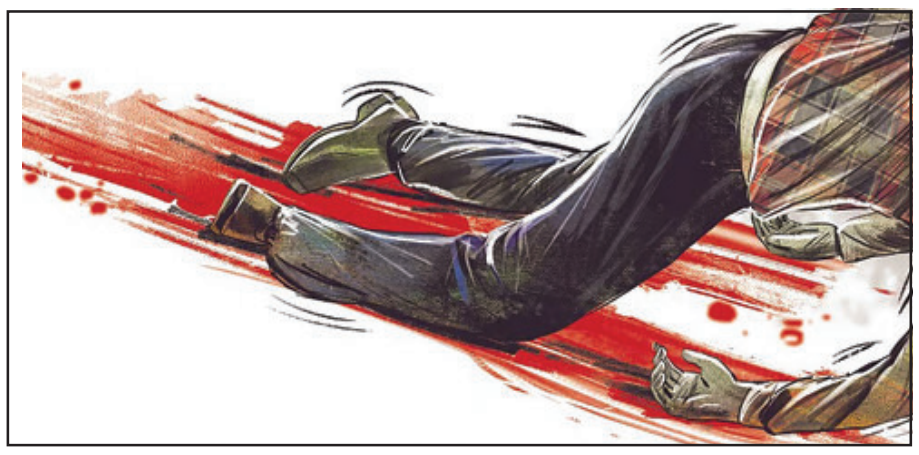

कैलगरी १३/०३ पंजाब के लुधियाना जिले के दंपती जैस्मीन कौर और एकमवीर सिंह की कनाडा के कैलगरी शहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने उनके शव घर में खून से लथपथ हालत में पाए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दावा किया जा रहा है कि दंपती को गोली लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही कैलगरी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों संभावनाओं पर जांच कर रही है। जैस्मीन कौर और एकमवीर सिंह मूल रूप से लुधियाना के जगराओं क्षेत्र के चौकीमान गांव के निवासी थे। बेहतर भविष्य की तलाश में वे कनाडा गए थे। उनके माता–पिता का पहले ही निधन हो चुका थे। चौकीमान गांव के सरपंच केवल सिंह ने कहा, "कोई कह रहा है कि दोनों को गोली लगी है, तो कोई मान रहा है कि आत्महत्या हुई है। सच्चाई का पता केवल पुलिस ही लगा सकती है।" सरपंच ने यह भी बताया कि एकमवीर सिंह के माता–पिता की काफी समय पहले मौत हो गई थी। इसके बाद उनका भाई अपने नाना के घर में रहने लगा। एकमवीर कभी–कभी ही गांव आता था। कैलगरी पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के सही कारणों का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस घटना से संबंधित कोई जानकारी हो तो 403–266–1234 पर संपर्क करें। गुमनाम सूचना देने के लिए क्राइम स्टॉपर्स 1–800–222–8477 पर कॉल किया जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, पंजाब में एक ही परिवार के सात सदस्यों में रेबीज के मिले लक्षण, 1 साल पहले एक को कुत्ता काटा था

लुधियाना। लुधियाना जिले के जगराओं क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के सात सदस्यों में रेबीज जैसे गंभीर लक्षण पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया।

सभी मरीजों को जगराओं के सिविल अस्पताल में प्राथमिक जांच के बाद गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवार के एक सदस्य को करीब एक वर्ष पहले कुत्ते ने काटा था। उस समय एंटी–रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई गई।

घाव भर जाने के बाद मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब हाल के दिनों में परिवार के अन्य सदस्यों में भी रेबीज से मिलते–जुलते लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद सभी को अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि यह परिवार जगराओं के शेरपुरा चौक के पास रहता है। परिवार का मुखिया एक फैक्ट्री में काम करता है।

उसके साथ उसकी पत्नी, तीन बच्चे और साली के दो बच्चे रहते हैं। साली के बच्चे भी पिछले एक वर्ष से इसी घर में रह रहे थे। सातों में समान लक्षण सामने आने से संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। सिविल अस्पताल जगराओं की एसएमओ डॉ. गुरविंदर कौर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी सात मरीजों को अत्यधिक लार आना, बोलने में दिक्कत और बेचैनी जैसे लक्षण थे। प्रारंभिक तौर पर ये लक्षण रेबीज की ओर इशारा कर रहे थे, इसी कारण देरी किए बिना उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेबीज की अंतिम पुष्टि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि कुत्ते या किसी भी जानवर के काटने की स्थिति में तुरंत एंटी–रेबीज वैक्सीन लगवाएं और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, क्योंकि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है।

ध्रुव पांडेव की याद में पटियाला में रक्तदान शिविर का आयोजन, 167 लोगों ने किया योगदान

पटियाला १३/०३ महान क्रिकेटर ध्रुव पांडेव की याद में आज ध्रुव पांडेव क्रिकेट ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 167 खिलाड़ियों और नागरिकों ने रक्तदान कर इस नेक कार्य में भाग लिया। ध्रुव पांडेव क्रिकेट ट्रस्ट की स्थापना युवा क्रिकेटर ध्रुव पांडेव की याद में की गई थी, जिनका 30 जनवरी 1992 को अंबाला के पास सड़क हादसे में निधन हो गया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेली और सबसे कम उम्र में शतक बनाने तथा 1,000 प्रथम श्रेणी रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। ध्रुव पांडेव बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और दाएं हाथ के प्रभावशाली लेग स्पिन गेंदबाज थे। वे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के समकालीन थे और भारतीय यूथ टीम के साथ एशिया कप जीत चुके थे। शिविर का उद्घाटन स. सुखमिंदर सिंह चौहान (AIG–एक्साइज और टैक्सेशन, पंजाब) ने किया। पंजाबी फिल्म जगत की प्रसिद्ध हस्तियां स. हॉबी ढालिवाल और श्रीमती सुनीता धीरण ने भी युवा रक्तदाताओं को इस नेक कार्य के लिए बधाई दी।

ट्रस्ट जरूरतमंद क्रिकेटरों और खेल से जुड़े अन्य व्यक्तियों की मदद भी करता है। इस शिविर के सफल आयोजन में श्री नरिंदरपाल वर्मा (लल्ली), प्रधान जिला केमिस्ट एसोसिएशन पटियाला और अन्य समाजसेवी का विशेष योगदान रहा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक स्वागतयोग्य : डॉ. सुभाष शर्मा

चंडीगढ १३/०३ पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला समाज के बड़े वर्ग के लिए राहत लेकर आया है। उन्होंने कहा कि इन नियमों को लेकर लोगों के मन में आशंका थी कि इनके दुरुपयोग की संभावना बन सकती है और इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को भी निशाना बनाया जा सकता है। डॉ. शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से समाज में फैली शंकाओं को स्पष्ट रूप से दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी कानून या नियम का उद्देश्य समाज में न्याय और समानता स्थापित करना होना चाहिए, न कि किसी निर्दोष को परेशान करना। उन्होंने कहा कि समाज में आपसी भाईचारा, समरसता और एकजुटता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मोदी सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव न हो और इसके विरुद्ध सख्त प्रावधान किए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति पर कोई आंच न आए। डॉ. सुभाष शर्मा ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार नए नियमों को पूरी संवेदनशीलता और संतुलन के साथ पुनः तैयार करेगी, ताकि न तो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिले और न ही किसी निर्दोष को लक्ष्य बनाया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान में ऐसा क्या है जिसका सवर्ण कर रहे हैं विरोध? समानता के नियमों को लेकर क्यों मचा बवाल?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नए नियमों को लेकर देश में राजनीति तेज हो गई है। इन नियमों के लागू होते ही सवर्ण समुदाय की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी हैं और इसके खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं।

सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक यह दावा किया जा रहा है कि यह रेगुलेशन एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने के लिए लाया गया है और इसका दुरुपयोग कर छात्रों और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा। कई मंचों से भय का वातावरण बनाया जा रहा है और तथ्यों से परे जाकर तरह तरह का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भावनात्मक शोर और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर इन नियमों की वास्तविकता को समझा जाए। सवाल उठता है कि आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है जिससे कुछ लोग डरे हुए हैं और क्या सचमुच यह किसी समुदाय के खिलाफ हैं? या फिर यह उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से चली आ रही असमानता और भेदभाव की समस्या से निपटने की एक कोशिश मात्र है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और यूजीसी के इन नियमों की सच्चाई आपके सामने रखने की एक कोशिश इस रिपोर्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026) को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य परिसर में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाना और वंचित सामाजिक समूहों को संस्थागत सहारा देना है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य होगा। यह केंद्र न केवल भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा, बल्कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगा। विविधता और समावेशन को बढ़ावा देना भी इसकी मुख्य जिम्मेदारी होगी।

जिन महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, वहां यह कार्य संबद्ध विश्वविद्यालय के समान अवसर केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इन नियमों के लागू होने की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2012 में बने भेदभाव विरोधी नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी को अद्यतन नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। यह याचिका रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा दायर की गई थी। हम आपको याद दिला दें कि इन दोनों ही छात्रों के मामलों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न और संस्थागत उदासीनता को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ी थी। नए ढांचे के तहत समान अवसर केंद्र के साथ एक समानता समिति का गठन भी अनिवार्य होगा। इस समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और उसे प्रत्येक छह महीने में अपनी रिपोर्ट संस्थान तथा यूजीसी को भेजनी होगी। इसके अतिरिक्त, परिसर में भेदभाव की रोकथाम के लिए छोटी सतर्कता इकाइयों के रूप में समानता दस्तों का गठन भी किया जाएगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि समान अवसर केंद्र स्थानीय प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समूहों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा सके। प्रत्येक संस्थान में एक वरिष्ठ शिक्षक को इस केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया जाएगा, जिसे वंचित समूहों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध माना गया हो। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो यूजीसी के पास कड़ी कार्रवाई के अधिकार होंगे।

इसमें यूजीसी की योजनाओं से वंचित करना, डिग्री और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को रोकना, यहां तक कि संस्थान को यूजीसी की मान्यता सूची से हटाना भी शामिल है।

इस बीच, इन नियमों के लागू होने के साथ ही देश के कुछ हिस्सों में विरोध के स्वर भी सुनाई दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह कदम लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, शनिवार 14 मार्च 2026

भुवनेश्वर नगर निगम का 2026-27 के लिए 1,050 करोड़ का ड्राफ़्ट बजट पेश किया

भुवनेश्वर १३/०३ (संवाददाता): भुवनेश्वर नगर निगम ने बुधवार को मेयर सुलोचना दास की अध्यक्षता में क्र्ष्ट मुज़्यालय में हुई 38वीं जनरल काउंसिल की बैठक में विज़ीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना 1,050 करोड़ का ड्राफ़्ट बजट पेश किया।

ड्राफ़्ट बजट के अनुसार, सिविक बॉडी को अपने राजस्व से 300 करोड़ मिलने की उज़्मीद है, जबकि 750 करोड़ राज्य सरकार से मिलेंगे।

परिषद को संबोधित करते हुए, मेयर सुलोचना दास ने भुवनेश्वर नगर निगम के आंतरिक राजस्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, और कहा कि बढ़ी हुई कमाई का सीधा असर 15वें और 16वें विज़ आयोग के तहत मिलने वाले अनुदान की मात्रा पर पड़ेगा।उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा नियमों का सज़्ती से पालन करने और राजस्व संग्रह तंत्र को मजबूत करने की सलाह दी। मेयर ने आगामी विज़ीय वर्ष के अंत तक सभी वार्डों में वार्ड कार्यालयों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा। एक बड़े फैसले में, जनरल काउंसिल ने भुवनेश्वर नगर निगम सीमा के भीतर गुटखा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया।वेंडिंग जोन और OMFED बूथों पर गुटखा बेचने पर लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। यह प्रतिबंध सभी क्षेत्रों में सज़्ती से लागू किया जाएगा, और इसके लिए सघन प्रवर्तन अभियान चलाए जाएंगे।

परिषद ने शहर से गुटखा से संबंधित सभी होर्डिंग्स हटाने का भी फैसला किया। ऐसे विज्ञापन लगाने वाली एजेंसियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्र्ष्ट राज्य सरकार के गुटखा निषेध कानून को सज़्ती से लागू करेगी।

बैठक को संबोधित करते हुए, क्र्ष्ट कमिश्नर चंचल राणा ने इन्फोसिटी में आगामी पाठा उत्सव के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्षदों से सहयोग मांगा।उन्होंने सदन को सूचित किया कि खंडगिरी कुंभ मेला सुचारू रूप से चल रहा है और भगवान लिंगराज की जात्रा यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की।

राणा ने कहा कि 15वें विज़ आयोग से जल्द ही फंड मिलने की उज़्मीद है। सरकारी अनुदान का उपयोग गौशालाओं और बाजारों के नवीनीकरण के साथ-साथ सड़क और जल निकासी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। कुछ कार्यों के लिए टेंडर पहले ही फाइनल हो चुके हैं, जबकि अन्य वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया के तहत हैं।

सदन को सूचित किया गया कि राज्य सरकार अब किराए के परिसरों से संचालित होने वाले शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (।।ड्डष्ट) के लिए किराया नहीं देगी। इन केंद्रों को सरकारी या क्र्ष्ट के स्वामित्व वाली इमारतों में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि, सर्वसज़्मति से यह तय किया गया कि क्र्ष्ट के तहत कोई भी ।।ड्डष्ट बंद नहीं किया जाएगा। पंडारा के पास एक आधुनिक मछली बाज़ार पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। अधिकारियों को मॉनसून शुरू होने से पहले ड्डस्च्यष्टह्ह और रसूलगढ़ ड्रेनेज प्रोजेज़्ट पूरे करने के निर्देश दिए गए थे। शहर भर के बड़े और अंदरूनी नालों की डीसिल्टिंग भी बारिश के मौसम से पले पूरी करनी होगी।

चंद्रशेखरपुर कल्याण मंडप का रेनोवेशन जल्द ही शुरू होगा। परिषद ने अगले 30 दिनों के भीतर हाटापोड़ी नंबर 1 प्रोजेज़्ट से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर भी चर्चा की।बैठक में डिप्टी मेयर मंजुलता कहार, क्र्ष्ट कमिश्नर चंचल राणा, विज़ और कराधान स्थायी समिति के अध्यक्ष राजकिशोर दास, सिटी इंजीनियर नारद चंद्र रथ, अतिरिक्त कमिश्नर रत्नाकर साहू और कैलाश चंद्र दास, और मुज़्य विज़ अधिकारी दीपक रंजन बेहरा मौजूद थे।

आलोक वर्मा ने जोल्डा 'सी' ज़्लॉक में आरएसपी की सीएसआर पहलों की समीक्षा

राउरकेला १३/०३ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के निदेशक-भारी, श्री आलोक वर्मा ने कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), श्री तरुण मिश्र के साथ जोल्डा 'सी' ज़्लॉक का दौरा कर क्षेत्र में संचालित सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा की। उनके साथ महाप्रबंधकङ्कप्रभारी (सीएसआर), सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक (सीएस आर) श्री बिभाबसु मलिक तथा संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। जोल्डा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि श्री इग्नेस खड़िया एवं श्री जत्रु ओराम ने निदेशक प्रभारी को क्षेत्र में संचालित विभिन्न ग्राम विकास गतिविधियों की जानकारी दी।

दौरे के दौरान निदेशक प्रभारी ने पुनर्वास कॉलोनी के निवासियों को उपलज़्ध कराई जा रही पेयजल सुविधाओं का अवलोकन किया तथा स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने में उनकी प्रभावशीलता का आकलन किया।

इसके पश्चात उन्होंने आरएसपी की सीएसआर पहल के अंतर्गत उषा सिलाई एवं ग्राम उत्थान के सहयोग से स्थापित जोल्डा स्थित प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) का भी भ्रमण किया। उन्होंने केंद्र में कार्यरत महिलाओं से बात-चीत की, कौशल विकास एवं आजीविका सृजन में उनके प्रयासों की सराहना की तथा ऐसी पहलों की निरंतर सफलता हेतु हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके उपरांत उन्होंने जोल्डा फुटबॉल मैदान का भी दौरा किया, जिससे क्षेत्र में खेल एवं युवाओं की सहभागिता को प्रोत्साहन मिल सके।

इस दौरे ने पार्श्वांचल क्षेत्रों में सामुदायिक कल्याण एवं सतत विकास के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता को पुन: सुदृढ़ किया।

एनआईए भुवनेश्वर ज़्लास्ट की जांच कर रही है, बड़ी साज़िश का शक

भुवनेश्वर १३/०३ (संवाददाता): नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए ने भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा इलाके में कल हुए धमाके की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बुधवार को घर के मालिक और कई अन्य लोगों से पूछताछ की, उन्हें शक है कि धमाके के पीछे कोई बड़ी साज़िश हो सकती है। यह घटना दोपहर में सुंदरपाड़ा के आज़ाद नगर में हुई, जब कथित तौर पर बम बनाए जा रहे थे। एक ज़ोरदार धमाके में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस जगमोहन मीना ने कहा कि धमाके में घायल सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, और ठीक होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने आगे बताया कि बम बनाने में कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ पहले से ही राज्य की राजधानी के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कम से कम सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि ज़्या विस्फोटक किसी अपराध को अंजाम देने के लिए तैयार किए जा रहे थे। ष्ठष्टक्क जगमोहन मीना ने पुष्टि की कि कई एंगल से जांच चल रही है। ष्ठष्टक्कने कहा, शुरुआती जांच, एक साइंटिफिक टीम द्वारा मौके की जांच, सीनियर अधिकारियों के दौरे और आपराधिक रिकॉर्ड से यह पता चला है कि जो लोग बम बना रहे थे, वे ही धमाके के लिए ज़िज़्मेदार हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ष्ठष्टक्क मीना ने कहा, 卐हम घायल लोगों की निगरानी कर रहे हैं ज़्योंकि उनका इलाज चल रहा है, और चोटों से ठीक होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सरकार ने ने कहा, चूंकि इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, इसलिए हमें शक है कि वे कोई अपराध करने के लिए बम बना रहे थे। गहन तलाशी के दौरान, मौके से कुछ आपज़िजनक सामग्री, जिसमें विस्फोटक के अवशेष भी शामिल हैं, बरामद और ज़ज़्त किए गए हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बताया, चार घायलों में शाहनवाज़ मलिक, उसकी मां, उसकी महिला दोस्त और सहयोगी अमिया रंजन मल्लिक शामिल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। मुज़्य आरोपी शाहनवाज़ एक हिस्ट्री-शीटर है और उसके खिलाफ नयापल्ली, मैत्री विहार और भुवनेश्वर के अन्य पुलिस स्टेशनों में कई मामले पेंडिंग हैं। वह हत्या की कोशिश और विस्फोटकों से जुड़े आपराधिक मामलों में शामिल था। गौरतलब है कि मंगलवार को भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा इलाके में एक धमाका हुआ, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह धमाका एयरफील्ड पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ।

बीजेडी ओडिशा में राज्य के किसानों की नौकरियों पर चर्चा करेगी

भुवनेश्वर १३/०३ (संवाददाता): बीजेडी ने कहा कि पार्टी ने संसद के आने वाले बजट सत्र के दौरान किसानों की परेशानी, कानून-व्यवस्था की चिंता, बेरोजगारी और राज्यों के बीच पानी के अनसुलझे विवादों जैसे कई मुद्दों को उठाने का फैसला किया है। नई दिल्ली में बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, बीजेडी राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, हमारे पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक के निर्देशानुसार, इस सत्र के दौरान दो प्रमुख मुद्दे उठाए जाएंगे। पहला किसानों और उनके कल्याण से संबंधित है और दूसरा कानून-व्यवस्था की स्थिति से संबंधित है।बीजेडी ने मंडियों को खोलने में देरी, अनियमित संचालन और धान की अनुचित कटौती के कारण धान खरीद संकट को उजागर करने का फैसला किया है, जिससे किसानों में भारी परेशानी हुई है।

सरकार ने 52 हजार करोड़ रुपये के निवेश का इरादा हासिल किया

राउरकेला १३/०३ (संवाददाता): यहां एंटरप्राइज ओडिशा 2026 में मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में तीन महत्वपूर्ण राउंडटेबल बैठकें हुईं, जिनमें 43,349 करोड़ रुपये के 22 स्नस्न पर हस्ताक्षर किए गए और पांच निवेश प्रस्ताव मिले। मुज़्यमंत्री ने राउरकेला चैंबर ऑफ कॉमर्स और ओडिशा स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (ह्रस्ढ्ढरू) के साथ राउंडटेबल चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने रांची और रायपुर के प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी विशेष बातचीत की। इन राउंडटेबल बैठकों से कुल 52,026 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 20,427 लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। इस मौके पर, माझी ने 5,708.00 करोड़ रुपये के निवेश वाली 11 औद्योगिक परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिससे 4,183 लोगों को रोज़गार मिलेगा। 3,176.00 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। ये परियोजनाएं 2,649 लोगों के लिए रोज़गार पैदा करेंगी और क्षेत्र में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

आरएसपी के सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव-2026 में कचारू गाँव के मालती ओराँव समूह ने चैंपियनशिप का खिताब जीता

राउरकेला १३/०३ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सिविक सेंटर में आयोजित सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव के अंतिम चरण में कुआरमुंडा ज़्लॉक के कचारू गाँव के मालती ओराँव समूह ने चैंज़्पियन का खिताब अपने नाम किया। निदेशक-प्रभारी (आरएसपी), श्री आलोक वर्मा समापन समारोह के मुज़्य अतिथि थे । इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक (संकार्य), श्री बिस्वरंजन पल्लई, कार्यपालक निदेशक (खान-ओजीओएम, सीएमएलओ), श्री एम पी सिंह, मुज़्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएँ एवं सीएसआर), श्री टी जी कानेकर, महाप्रबंधक-प्रभारी (सीएसआर), सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक (सीएस आर), श्री बिभाबासु मल्लिक, आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच, कार्यक्रम के निर्णायक, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा राउरकेला के चार पार्श्वांचल ज़्लॉकों के प्रतिभागी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व ज़्लॉक स्तर पर आयोजित क्षेत्रीय चरणों में लाठीकाटा ज़्लॉक, नुआगाँव ज़्लॉक, बिसरा ज़्लॉक और कुआरमुंडा ज़्लॉक के विभिन्न गांवों से कुल 120 दलों ने भाग लिया था। प्रत्येक ज़्लॉक से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दलों ने अंतिम चरण में चैंज़्पियनशिप खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए ।

श्री वर्मा ने सभी प्रतिभागी दलों और विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि मंच पर उतरकर अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करना, अपने आप में एक बड़ी उपलज़्धि है। उन्होंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसे आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक विकास सभी को साथ लेकर चलने में निहित है और सीएसआर केवल एक संगठनात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि सामूहिक जिज़्मेदारी और जीवन का अभिन्न अंग है। निदेशक-प्रभारी ने आगामी वर्षों से पुरस्कार राशि में वृद्धि की भी घोषणा की।

इस अवसर पर अतिथियों ने नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए। कुआरमुंडा ज़्लॉक के कचारू गाँव के मालती ओराँव समूह ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 20,000/- रुपये की नकद राशि और चैंज़्पियन ट्रॉफी प्राप्त की। बिसरा ज़्लॉक के सरूबहाल गाँव के लक्ष्मी समूह को 17,500/- रुपये की नकद राशि और ट्रॉफी के साथ द्वितीय पुरस्कार मिला। लाठीकाटा ज़्लॉक के उड़सू गाँव के संजीता नृत्य मण्डली ने 15,000/- रुपये की नकद राशि और ट्रॉफी के साथ तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। सभी विजेता समूहों को पुरस्कारों के साथ प्रतिक उपहार के रूप में फोटो फ्रेम भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर निर्णायकों को भी सज़्मानित किया गया। इसके अलावा, शेष प्रतिभागी दलों को 5,000/- रुपये की सांत्वना राशि प्रदान की गई। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग आदिवासी स्वागत नृत्य से हुई, जिसके बाद चयनित नृत्य दलों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक प्रस्तुतियों की झलकियां अतिथियों के समक्ष दिखाई गईं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुज़्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएँ एवं सीएसआर), श्री टी जी कानेकर, ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सीएसआर गतिविधियों की जानकारी दी। सुश्री मुनमुन मित्रा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समन्वय सहायक महाप्रबंधक (सीएस आर), श्री टी बी टोप्पो, ने किया, जबकि पुरस्कार समारोह का समन्वय वरिष्ठ फील्ड सहायक (सीएसआर), श्री बी एक्का द्वारा किया गया।

उल्लेखनीय है कि अपनी सीएसआर पहलों के तहत आरएसपी वर्ष 2012-13 से सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है।